GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

S.No. PC-V/99 **RBE No. 163/98**
No. PC-V/97/I/RSRP/1 **New Delhi, dated 17 .7.98**

The General Manager/CAO(R)/OSD
All Indian Railways & PUs
(As per standard mailing list)

Sub : Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 - Clarifications regarding.

A number of references have been received from various Railways seeking clarifications on the precise import of some of the provisions of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 notified vide GSR 584(E) dated 8th October, 1997 and the manner in which pay is to be fixed or increments regulated under certain circumstances. The necessary clarifications are furnished below:

Point raised	**Clarification**
1. In terms of the third proviso to Rule 7, in fixing the pay of an employee in the revised scale of pay, it is to be ensured that he gets at least one increment in the revised scale of pay for every three increments (inclusive of stagnation increments, if any) drawn by him in the existing scale of pay. It is not clear when the next increment should be granted in such cases.	The next increment in such cases shall be granted on the date the employee would normally have drawn his increment had he continued in the pre-revised scale of pay. It is further clarified that in cases where the pay of an employee is stepped up with reference to the pay of his junior in terms of the second proviso to sub-rule (1) of Rule 7 or Note 6 or Note 9 thereunder, the next increment shall be admissible only on the employee completing 12 months of qualifying service from the date his pay is stepped up in the revised scale of pay.
2. Date of next increment in the revised scale of pay in cases where an employee has reached the maximum of the applicable pre-revised scale or has been stagnating at the maximum for more than a year as on 1st January 1996.	It appears that there has been some confusion about the manner in which the next increment is to be regulated in respect of employees who have drawn stagnation increments in the pre-revised pay scales. In these cases, the pay of the employees is to be fixed initially in the revised scale in terms of the provisions of Rule 7 after allowing the benefits of bunching or of one increment for every three increments earned in the pre-revised scale as the case may be. Thereafter, if the employees have also been stagnating for more than one year at the maximum of the pre-revised scale or have drawn one or more stagnation increments as admissible, they may also be allowed an additional increment on 1st January, 1996 itself in terms of the third proviso to Rule 8. The subsequent increment in such cases shall be admissible on 1st January, 1997. The benefit of an additional increment on 1st January, 1996 shall also

...2/-

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं.: पी.सी.5/99 कोर की ई.सं.: 163/98

सं0 पी.सी.5/97/आई/आर.एस.आर.पी/1 नयी दिल्ली, दिनांक : 17.7.98

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(रेलें)/विशेष कार्याधिकारी,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां.
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय:- रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के संबंध में स्पष्टीकरण.

xxxxxxxx

विभिन्न रेलों से अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें 8 अक्टूबर,1997 के जी.एस.आर.584(ई) द्वारा अधिसूचित रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के कुछ उपबंधों तथा कतिपय परिस्थितियों में निर्धारित किए जाने वाले वेतन अथवा विनियमित किए जाने वाले वेतनवृद्धि के तरीके के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गये हैं. आवश्यक स्पष्टीकरण नीचे दिए गये हैं:-

उठाए गए मुद्दे	स्पष्टीकरण
1. नियम 7 के तीसरे परंतुक के अनुसार संशोधित वेतनमान में किसी कर्मचारी का वेतन निर्धारण करने में, यह सुनिश्चित करना होता है कि मौजूदा वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाली प्रत्येक तीन वेतनवृद्धियों (गतिरोध वेतनवृद्धि सहित, यदि कोई हो) के लिए उसे संशोधित वेतनमान में कम से कम एक वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है. यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे मामलों में कब अगली वेतनवृद्धि प्रदान करनी चाहिए.	इस प्रकार केमामलों में अगली वेतनवृद्धि उसीतारीख को प्रदान की जाएगी जिस तारीख को उसने अपने पूर्व संशोधित वेतनमान में बने रहने पर इसे प्राप्त किया होता. आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उन मामलों में जहां किसी कर्मचारी का वेतन,नियम 7 के उप नियम (1) के दूसरे परंतुक अथवा इसके अंतर्गत नोट 6 या नोट 9 के अनुसार उसके कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर बढ़ाया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि केवल उसी कर्मचारी को स्वीकार्य होगी जिसने संशोधित वेतन में, अपना वेतन बढ़ाये जाने की तारीख से अर्हक सेवा के 12 महीने पूरे कर लिए हों.

S.No. PC-V/99

be admissible to those employees who reached the maximum of their pre-revised scale of pay on 1st January 1995.

3. Manner in which pay in the revised scales is to be fixed in cases where the 'existing emoluments' computed after adding an amount representing 40 percent of the basic pay in the pre-revised scales in terms of sub-rule (1)(A)(i) of Rule 7 exceed the maximum of the applicable revised scales.

The pay in the applicable revised scale is to be fixed in such cases *only* at the maximum of that scale as provided in Rule 7(1)(A)(b) and no personal pay is to be allowed in addition to compensate for the difference between the maximum of the revised scale and the amount arrived at after adding the fitment benefit of 40 percent to the 'existing emoluments'.

4. Manner of payment of arrears on account of revision of scales of pay and allowances in respect of those employees who have superannuated on or after 1st January 1996.

In terms of Rule 11 of the RSRP Rules, 1997 read with Explanation (b) thereunder, all arrears accruing for the relevant period, i.e. the period from 1st January 1996 to 30th September 1997 are to be paid only in two instalments as provided therein; no distinction is to be made in this regard between serving and superannuated employees. An exception may, however, be made in cases where an employee has expired before being paid the arrears due on account of revision of pay scales and allowances. In such cases, the arrears may be paid in lumpsum to the legal heirs of the deceased employee.

2. Hindi version is enclosed.

(Neera Khuntia)
Director, Pay Commission

No. PC-V/97/I/RSRP/1 **New Delhi, dated** 17 .7.98

Copy to :

ADAI (Railways), Mathura Road, New Delhi (with 40 spares)

for Financial Commissioner

Copy forwarded to :-

1. The GM N.F. Railway (Const.), CAOs, Southern Railway (Const.) and Central Railway(Const.)
2. The FA & CAOs, All Indian Railways, Production Units, N.F. Railway (Const.) and Southern Railway (Const.)
3. The Director General, RDSO/Lucknow
4. The General Manager and FA & CAO, Metro Railway/Calcutta
5. The General Manager and FA & CAO, COFMOW/New Delhi
6. The General Manager and FA & CAO, CORE/Allahabad
7. The Principal, Railway Staff College/Vadodara
8. The CAO (Const.), MTP(K)/Mumbai
9. The CAO (Const.), MTP(R)/Chennai
10. The Director, CAMTECH/Gwalior-474020
11. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad
12. The Managing Director, RITES, IRCON, IRFC, CONCOR of India Limited, Executive Director, CRIS
13. The Chairman and Managing Director, KRC Limited/New Delhi
14. Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom (IRCOT) Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi
15. The Director (Movement), Railways/Calcutta

rudra/rsrp/2

2. उन मामलों में वेतनवृद्धि की अगली तारीख क्या होगी जहां कोई कर्मचारी लागू पूर्व-संशोधित वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंच चुका हो अथवा 1 जनवरी,1996 को एक वर्ष से अधिक समय से इस अधिकतम स्तर पर बना हुआ हो.

ऐसा प्रतीत होता है कि उन कर्मचारियों जिन्होंने पूर्व-संशोधित वेतनमान में गतिरोध वेतनवृद्धिप्राप्त की हो,के संबंध में विनियमित किए जाने वाले वेतनवृद्धि के तरीके के बारे में कुछ भ्रम है. ऐसे मामलों में, कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण समूहीकरण (बंचिंग) का लाभ प्रदान करते हुए अथवा पूर्व संशोधित वेतनमान में,अर्जित प्रत्येक तीन वेतनवृद्धियों के लिए एक वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए,जैसा भी मामला हो नियम 7 के उपबंधों के अनुसार प्रारंभ में संशोधित वेतनमान में करना होता है. इसके पश्चात् यदि कोई कर्मचारी पूर्व संशोधित वेतनमान के अधिकतम स्तर पर एक से अधिक वर्ष से रुका रहा हो अथवा जिन्होंने यथास्वीकार्य एक या दोगतिरोधता वेतनवृद्धि प्राप्त की हो उन्हें भी नियम8 के तीसरेपरंतुक के अनुसार, 1 जनवरी,1996 से ही एक और वेतनवृद्धि स्वीकार्य होगी. ऐसे मामलों में उत्तरवर्ती वेतनवृद्धि 1 जनवरी,1997 को स्वीकार्य होगी. एक जनवरी 1996 को एक और वेतनवृद्धि उन कर्मचारियों को भी स्वीकार्य होगी जो 1 जनवरी,1995 को अपने पूर्व-संशोधित वेतनमान में अधिकतम स्तर पर पहुंच चुके हों.

3. उन मामलों में संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारित किए जाने का तरीका, जहां नियम 7 के उप नियम (1)(ए)(1) के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान में मूल वेतन की 40% राशि जोड़ने के बाद परिकलित "मौजूदा परिलब्धियां" लागू संशोधित वेतनमान के अधिकतम स्तर से अधिक बनती हों.

इस प्रकार के मामलों मे लागू संशोधित वेतनमान में वेतन का निर्धारण नियम 7(1)(ए)(बी) में यथाउपबंधित उस वेतनमान के अधिकतम स्तर पर ही करना होता है तथा संशोधित वेतनमान के अधिकतम स्तर तथा "मौजूदा परिलब्धियों" में 40% का फिटमेंट लाभ जोड़ने के बाद प्राप्त राशि के बीच अन्तर की क्षतिपूर्ति करने हेतु अतिरिक्त वैयक्तिक वेतन की अनुमति नहीं होगी.

4. 1 जनवरी,1996 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में वेतन एवं भत्ते में संशोधन किए जाने के कारण बकायों के भुगतान

रेल सेवा संशोधित वेतन नियम,1997 के अंतर्गत स्पष्टीकरण (२८) के साथ पठित नियम 11 के अनुसार संगत अवधि अर्थात् 1 जनवरी,1996 से 30 सितम्बर,1997 तक उपार्जित सभी बकायों का भुगतान इसमें यथा

क्र.स.जी.ती.5/99

का तरीका.

उपबंधित के अनुसार केवल दो किस्तों में किया जाना है तथा इसमें सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं करना होता है. लेकिन, उन मामलों में एक अपवाद हो सकता है जहां किसी कर्मचारी की मृत्यु वेतनमान एवं भत्तों में संशोधन किए जाने के कारण बकाये के भुगतान किए जाने से पूर्व हो गयी हो. ऐसे मामलों में मृतक कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को बकाये का भुगतान एक मुश्त किया जाए.

नीरा खुटिया
निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड.

[वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कार्यालय ज्ञापन सं. 50(4)/97/IC-I दिनांक 2.4.98]